मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

जलभराव से 'निपटने' का बीड़ा उठाया उपायुक्त ने	2
ईएसआई पैसा लेना जानती है सुविधायें देना नहीं	4
राहुल लिए गये ईडी के निशाने पर	5
पीएम मोदी हैं अडानी-अंबानी के ब्रोकर!	6
सीवेज से प्रदूषित हो रहा नदी व नहरों का पानी	8

वर्ष 36 | अंक 32 | फरीदाबाद | 19-25 जून 2022 | फोन-8851091460 | 5.00 ₹

अग्निपथ की आग में जल गए मोदी

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

नये-नये आकर्षक नाम गढ़ने में माहिर मोदी गिरोह ने देश की युवाओं को रोजगार देने के नाम पर अग्निपथ नाम से एक जाल फैलाया है। इसमें फंसने वालों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। लेकिन देश के युवा इतने मूर्ख नहीं रह गये हैं जो मोदी गिरोह की इस चाल को न समझ सकें। इसलिये इसके विरोध में तेलांगना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि तमाम राज्यों में युवा सड़कों पर उतर आये हैं।

बीते करीब तीन वर्षों से सेना में कोई भर्ती नहीं हो रही है। इसके चलते देश की थल सेना में 92 हजार सैनिकों तथा 13 हजार अफ़सरों के पद खाली पड़े हैं। विदित है कि देश के गरीब एवं साधनों से वंचित युवाओं के लिए फौज की नौकरी ही एकमात्र बाइज्जत रोजगार बचा है। इसके लिए इन वर्गों के युवक कड़ी मेहनत करके अपने आपको शारीरिक एवम् मानसिक रूप से सेना के लिए तैयार करते हैं। बीते तीन वर्ष से भर्ती न होने के कारण अनेकों युवक अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं।

इन युवाओं को बहलाने के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ नाम से योजना पेश की है। इसके द्वारा 17.5 साल की आयु 23 साल के युवाओं को मात्र चार वर्ष के लिए भर्ती किया जायेगा। इनमें से मात्र 25 प्रतिशत को स्थायी रूप से सेना में रखा गया जायेगा शेष को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा जिन्हें कोई पेंशन अथवा सेवा लाभ नहीं मिलेगा। कहने की जरूरत नहीं कि जो 25 प्रतिशत नियमिति सैनिक बन पायेंगे वे भी भरकम भ्रष्टाचार के शिकार हुआ करेंगे।

चार वर्ष के सेवाकाल में कोई भी युवक पूरी तरह ट्रेंड सैनिक भी नहीं बन पायेगा और इससे पहले ही वह रिटायर हो जायेगा। इस योजना के तहत मात्र छह महीने की ट्रेनिंग देकर, बंदूक पकड़ाकर उसे कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मरने के लिए झोंक दिया जायेगा। समझा जा सकता है कि यह नौसिखिये जवान जो अब ढंग से हथियार पकड़ना भी न जानते होंगे बेमौत मारे जायेंगे। सरकार उनकी मौत पर एक पीपनी बजाकर तथा मगरमच्छ के आंसू बहाकर श्रद्धांजलि का ढोंग कर देंगे।

लेकिन युवाओं ने इसे सिरे से नकार दिया। विरोध प्रकट करने के लिए युवाओं ने जो रास्ता अख्तियार किया है उसे गैरकानूनी एवम् हिंसक बताया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। बात काफी हद तक सही भी है लेकिन प्रदर्शनकारियों का इसे देखने का नजरिया कुछ दूसरा है। वे रेलें, बसे एवम् अन्य सरकारी सम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त करके सरकार की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उनके हाथ शासक वर्ग के किसी बड़े नेता के गले तक पहुंचने में तो समर्थ हैं नहीं इसलिए वे इस तरह के हिंसक आंदोलन का सहारा लेने को मजबूर है। उनका मानना है कि सरकार इसके अलावा कोई और भाषा समझती भी नहीं है। जब पीड़ित का अपने से जाबर पर वश नहीं चलता तो वे अपने को ही मारकर अपना रोष प्रकट करता है। यही सब कुछ आज का आक्रोषित युवा कर रहा है।

फौज की भर्ती के नए नियमों के विरुद्ध पुलिस की बेवकूफी से पलवल में चार घंटे चला उत्पात

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से गुस्साए युवाओं ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 जाम कर जमकर उपद्रव मचाया। युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए और जिला उपायुक्त निवास स्थान स्थित गार्ड रूम में आग लगा दी। उपद्रव में एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। भड़के युवाओं ने पुलिस की पांच गाड़ियों को भी जला दिया। करीब तीन घंटे बाद दूसरे जिलों से आई पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया।

बृहस्पतिवार की सुबह साढ़े नौ बजे सैंकड़ों की संख्या में युवा सबसे पहले शहर के बस स्टैंड पर जाकर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय की तरफ चल दिए। शहर के ताऊ देवीलाल पार्क के समीप जाकर युवा अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बैठ गए और आसपास लगी ग्रिलों व खंबों को उखाड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार, डीएसपी यशपाल खटाना, डीएसपी विजय पाल, डीएसपी सत्येंद्र ने प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर कोई बात नहीं बन सकी। इसके

शेष पेज 3 पर

हर काम का सेहरा अपने सिर बांधने वाले मोदी ने अग्निपथ राजनाथ के सिर मढा

आज तक चाहे कोरोना की वैक्सीन लगनी हो, चाहे गैस का सिलैण्डर बांटना हो, चाहे पांच किलो अनाज देना हो, चाहे पेट्रोल के दाम पांच रूपए घटाने हो, हर चीज के लिए 'मोदी जी थैंक्यू' के नारे हवा में उछाले जाते रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी को काफी हद तक एहसास रहा होगा कि यह अग्निपथ उनके अग्नि परीक्षा बन सकता है। इसलिए इसकी घोषणा उन्होंने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से करवाई। राजनाथ सिंह ने भी यह घोषणा करते समय थोड़ी चतुराई दिखाते हुए अपने दांये-बांये तीनों सेना प्रमुख बिठा लिए। लानत है उन तीनों सेना अध्यक्षों को जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते भी इस सेना विरोधी कदम को अपनी मूक स्वीकृत्ति देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। कहने की जरूरत नहीं इन तीनों ने अपना सेवाकाल का उच्चतम पद हासिल कर लिया है और सेवानिवृत्ति के मुहाने पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने इस राष्ट्र विरोधी षडयंत्र में अपने आपको लिप्त कर लिया।

गौरतलब है कि पूर्व सेनाध्यक्ष एवम् मौजूदा केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की आत्मा शायद अभी पूरी तरह मरी नहीं है। वे मोदी भक्त तो जरूर है लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने अंधभक्त बनने से इंकार कर दिया। जब पत्रकारों ने इस योजना बाबत पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं। अभी तो मैंने इसके बाबत सुना है जब योजना धरातल पर आयेगी तब उसे देखा व समझा जा सकेगा। मामला स्पष्ट है जब एयर चीफ मार्शल व अन्य सरकारी भोंपू इस योजना की खुलकर वकालत एवम् तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे में जनरल वीके सिंह क्यों पीछे रह गये? अर्थ स्पष्ट है कि वह अपनी सेना व देश के साथ, मोदी के कहने पर गददारी नहीं कर सकते।

'अग्निपथ' हिंदुओं के सैन्यीकरण का कोई संघी प्रकल्प तो नहीं है !

अरुण माहेश्वरी

मोदी सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के एक अजीबोग़रीब प्रकल्प को अपनाया है। प्रकल्प को नाम दिया गया है-अग्निपथ। इस प्रकल्प में पहले 17 से 21 साल के कुछ हज़ार नौजवानों को छः महीनों के सैन्य प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा और बाद में उनमें से 25 प्रतिशत को चार साल के बाद सेना की नियमित टुकड़ियों में शामिल किया जायेगा।

नियमित सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण के अपने सख्त नियम और अवधि होती है। इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता सेना की दक्षता के साथ समझौता कहलायेगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई का कोई सैन्य औचित्य नहीं हो सकता है ।

तब सवाल उठता है कि आखिर यह किया क्यों जा रहा है, जिससे हमारी सेना की दक्षता साथ खिलवाड़ का ख़तरा पैदा होता है? ऊपर से, यह प्रकल्प सैनिकों के अंदर एक विभाजन भी पैदा करेगा। कुछ सैनिक एक साल के प्रशिक्षण वाले होंगे और कुछ सिर्फ़ छः महीनों के।

इससे स्वाभाविक तौर पर मोदी सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है। जो लोग भी आरएसएस और उसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं, वे जानते हैं कि हिन्दुओं का सैन्यीकरण आरएसएस के गठन के वक्त से ही उसका एक घोषित लक्ष्य रहा है। संघ के 'हिंदुत्व' का यह एक प्रमुख लक्ष्य है।

संघ के शिविरों में शस्त्र पूजा और लाठी भांजने आदि के कार्यक्रमों के पीछे मूलतः हमेशा यही लक्ष्य काम करता है । हर कोई जानता है कि मोदी जितने भारत के प्रधानमंत्री हैं, उससे अधिक आज भी संघ के प्रचारक बने हुए हैं । इसीलिए मुसलमानों के प्रति नफ़रत और हिंसा के हर अभियान को उनका मूक समर्थन रहता है ।

इसीलिए यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि कहीं मोदी सरकार के 'अग्निपथ' प्रकल्प का संघ के 'हिंदुओं के सैन्यीकरण' के कार्यक्रम से कोई संबंध तो नहीं है?

मोदी सरकार के अन्य कई अभियानों की तरह ही क्या यह राष्ट्र की क़ीमत पर संघ के कार्यक्रम पर अमल का कोई कदम तो नहीं है?

भारतीय सेना के खर्च पर तैयार किए जाने वाले 'अग्निवीर' भारत की रक्षा के लिए तैयार किए गए सैनिक होंगे या भारत में संघ के सांप्रदायिक एजेंडा पर काम करने वाले स्वयंसेवक ?

'अग्निपथ' प्रकल्प को बहुत गहराई से समझने और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है ।